कई देश विदेशी फंड नियंत्रित करते हैं

एफसीआरए बिल पर भारत का जवाब- यह हमारा आंतरिक मामला है

नई दिल्ली, 7 अगस्त. केंद्र सरकार ने विदेशी अंशदान विनियमन अधिनियम संशोधन विधेयक पर स्पष्ट किया है कि यह भारत का आंतरिक मामला है और किसी अन्य देश को इस विषय पर टिप्पणी करने का अधिकार नहीं है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस वार्ता में यह बात कही. उन्होंने कहा कि दुनिया के अनेक देशों, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, विदेशी फंडिंग और विदेशी अंशदान को नियंत्रित करने के लिए अपने-अपने कानून और नियामकीय व्यवस्थाएं लागू करते हैं. सरकार की यह प्रतिक्रिया अमेरिकी सांसद रिले एम. मूर की उस सोशल मीडिया टिप्पणी के बाद आई है, जिसमें उन्होंने एफसीआरए संशोधन विधेयक को ईसाइयों के खिलाफ बताया था. मूर ने 4 अगस्त को सोशल मीडिया मंच

एक्स पर लिखा था कि यदि यह विधेयक मौजूदा स्वरूप में पारित होता है तो इससे भारत और अमेरिका के द्विपक्षीय संबंध प्रभावित हो सकते हैं. सरकार के अनुसार, एफसीआरए संशोधन विधेयक को इसी वर्ष बजट सत्र के दौरान लोकसभा में पेश किया गया था और इस पर संसद के मानसून सत्र में चर्चा प्रस्तावित है. सूत्रों के मुताबिक, इस विधेयक पर होने वाली चर्चा का जवाब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दे सकते हैं. सरकार ने पहले ही स्पष्ट किया है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य विदेशी अंशदान के उपयोग में पारदर्शिता, जवाबदेही और राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना है. प्रस्तावित प्रावधानों के तहत विदेशी धन प्राप्त करने वाली संस्थाओं को अपने कार्यक्षेत्र और धन के उपयोग का स्पष्ट विवरण देना होगा. साथ ही, विदेशी अंशदान का उपयोग धर्म परिवर्तन के लिए नहीं किया जा सकेगा. एक अन्य प्रस्ताव के अनुसार, यदि किसी संस्था का एफसीआरए पंजीकरण समाप्त, निरस्त या रद्द हो जाता है, तो विदेशी अंशदान से अर्जित उसकी संपत्तियों के प्रबंधन और संरक्षण की जिम्मेदारी सरकार द्वारा नामित प्राधिकरण को सौंपी जा सकेगी.

> इस विधेयक को लेकर कुछ धार्मिक संगठनों और गैर-सरकारी संस्थाओं ने चिंता व्यक्त की है. उनका कहना है कि पंजीकरण संबंधी प्रक्रियाओं में छोटी त्रुटियों की स्थिति में कठोर कार्रवाई की आशंका बनी रह सकती है. हालांकि सरकार पहले ही स्पष्ट कर चुकी है कि प्रस्तावित संशोधन पूर्व प्रभाव (रेट्रोस्पेक्टिव) से लागू नहीं होंगे. संसदीय स्थिति के अनुसार, यह एक सामान्य विधेयक है, जिसे पारित कराने के लिए दोनों सदनों में साधारण बहुमत की आवश्यकता होगी.

सास को दामाद ने मार डाला

नई दिल्ली. यूपी के पीलीभीत जिले के अमरिया थाना क्षेत्र के जिठनिया गांव में रिश्तों को कलंकित कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. यहां एक दामाद पर अपनी ही सास की हत्या कर शव को बूंगे (उपलों के ढेर) में जलाकर साक्ष्य मिटाने का आरोप लगा है. घटना का खुलासा उस समय हुआ जब छह दिन से लापता महिला की तलाश में जुटे बेटे ने गांव वालों के साथ बूंगे की राख हटाई. राख में जली हुई हड्डियां और चूड़ियां मिलने के बाद पूरे गांव में हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी. बेटे की तहरीर पर आरोपी दामाद के खिलाफ हत्या और साक्ष्य मिटाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. थाना अमरिया क्षेत्र के गांव जिठनिया निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि उसकी 65 वर्षीय मां मोहनदेई गांव के बाहर कब्रिस्तान के पास बने अपने मकान में अकेली रहती थीं. परिवार के अन्य सदस्य गांव में अलग रहते हैं.

पीएम मोदी से मिले एकनाथ शिंदे

नई दिल्ली, 07 अगस्त. महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर मुलाकातों का सिलसिला चचाज़ के केंद्र में है. मुंबई में सुनेत्रा पवार की चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर से मुलाकात के एक दिन बाद महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने शुक्रवार सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली में मुलाकात की.

लगातार हो रही इन बैठकों ने महाराष्ट्र की सियासत में नई अटकलों को जन्म दे दिया है. सवाल उठ रहा है कि क्या महायुति के भीतर कोई नई राजनीतिक रणनीति तैयार हो रही है या ये मुलाकातें सामान्य राजनीतिक समन्वय का हिस्सा हैं. प्रधानमंत्री हाल के छात्र और युवा आंदोलनों के बाद विभिन्न एनडीए सहयोगी दलों के नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं. इसी क्रम में शिंदे के साथ महाराष्ट्र की राजनीतिक और प्रशासनिक स्थिति पर चचाज़ होने की बात सामने आई है. बैठक में महाराष्ट्र के मौजूदा राजनीतिक

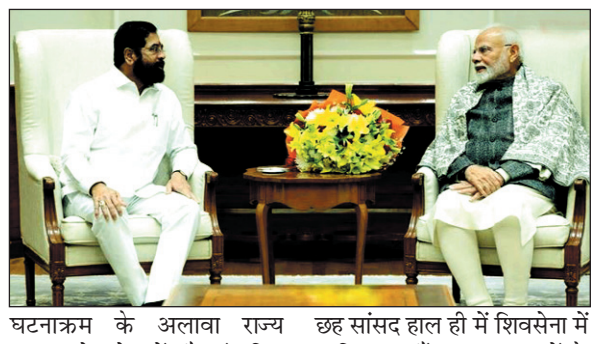

घटनाक्रम के अलावा राज्य सरकार से जुड़े मुद्दों और संभावित कैबिनेट विस्तार पर भी चचाज़ होने की अटकलें हैं. शिंदे की यह मुलाकात ऐसे समय हुई है, जब उद्धव बालासाहेब ठाकरे गुट के छह सांसद हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए हैं. इन घटनाक्रमों के बाद महाराष्ट्र में शिवसेना और महायुति के राजनीतिक समीकरणों को लेकर चचाज़ और तेज हो गई है.

> इससे पहले राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़णवीस की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी हुई थी. शिवसेना के कुछ सांसदों ने भी अमित शाह से मुलाकात की थी. इन बैठकों में सांसदों के निवाज़्चन क्षेत्रों से जुड़े विकास कायोज़ं समेत विभिन्न मुद्दों पर चचाज़ होने की जानकारी सामने आई थी. मुंबई में सुनेत्रा पवार और प्रशांत किशोर की मुलाकात ने भी राजनीतिक हलकों का ध्यान खींचा है. प्रशांत किशोर चुनावी रणनीति और राजनीतिक अभियानों के लिए जाने जाते हैं. ऐसे में उनकी सुनेत्रा पवार के साथ मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं. हालांकि, इस बैठक के एजेंडे या भविष्य की किसी राजनीतिक रणनीति से जुड़े होने की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है.

जमात गठबंधन का सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन

ढाका, 7 अगस्त. बंगलादेश में जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले 11 विपक्षी दलों के गठबंधन ने पूरे देश में विरोध प्रदर्शनों और ढाका में एक बड़ी रैली करने की घोषणा की है जिसका

- बांग्लादेश में विपक्ष का दबाव बढ़ा
- नवंबर में ढाका में बड़ी रैली

उद्देश्य बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के नेतृत्व वाली सरकार पर दबाव बनाना है ताकि वह जुलाई के 'नेशनल चार्टर' और जनमत संग्रह के फैसले को लागू करनके के साथ ही ईंधन, गैस एवं बिजली की कीमतें कम करे और देश में चल रहे महंगाई के संकट का समाधान करे.

ढाका के पलटन इलाके में मुक्तंगन में गुरुवार को धरने के दौरान गठबंधन के प्रमुख और जमात अमीर शफीकुर रहमान ने इन कार्यक्रमों की घोषणा की. ये कार्यक्रम गठबंधन द्वारा बताये गये मुद्दों पर केंद्रित हैं जिसमें ईंधन और गैस का संकट, बिजली के फर्जी बिल, बिगड़ती कानून-व्यवस्था और ज़रूरी चीज़ों की बढ़ती कीमतें शामिल हैं. शफीकुर के अनुसार, यह आंदोलन बड़े पैमाने पर हुई हत्याओं के लिए जम्मिदार लोगों पर तुरंत मुक़दमा चलाने, सार्वजनिक सुरक्षा को बेहतर बनाने और सरकारी संस्थानों पर संकीर्ण दलीय नियंत्रण को खत्म करने

सीएम विजय की पत्नी ने वापस ली तलाक की अर्जी

चेन्नई, 07 अगस्त. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री विजय के निजी जीवन से जुड़ा बहुचचिज़्त तलाक विवाद अब अदालत में खत्म हो गया है. उनकी पत्नी संगीता सोरनालिंगम ने चेंगलपट्टू फैमिली कोटज़ में दाखिल तलाक की अजीज़ शुक्रवार को वापस ले ली.

संगीता वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश हुईं. उन्होंने जज सुजाता को अपनी याचिका वापस लेने की जानकारी दी. इसके बाद जज ने करीब 15 मिनट तक उनसे पूछताछ की और उनकी अजीज़ स्वीकार करते हुए तलाक की कायज़्वाही समाप्त कर दी. संगीता ने इसी साल फरवरी में तलाक की याचिका दायर की थी. याचिका में उन्होंने विजय पर विवाहेतर संबंध होने का आरोप लगाया था. उन्होंने दावा किया था कि अप्रैल 2021 में उन्हें अपने पति के एक अभिनेत्री के साथ संबंधों के बारे में जानकारी मिली. इस घटना के बाद उन्हें मानसिक परेशानी हुई.

जेन जी का मन टटोलेगी योगी सरकार

लखनऊ, 07 अगस्त. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच युवाओं को लेकर सियासी रणनीति तेज हो गई है. योगी सरकार अब गेन जी यानी नई पीढ़ी के युवा मतदाताओं की नब्ज टटोलने की तैयारी में है.

- युवाओं पर योगी सरकार का फोकस
- स्वतंत्र आयोग करेगा निगरानी

इसके लिए सरकार 16 से 35 वषज़ की उम्र के युवाओं को ध्यान में रखते हुए एक स्वतंत्र युवा आयोग गठित करने की दिशा में आगे बढ़ रही है. प्रस्तावित आयोग के जरिए युवाओं की समस्याओं, अपेक्षाओं और सुझावों को समझने के साथ उन्हें सरकार की नीतियों से जोड़ने की कोशिश की जाएगी.

युवा वगज़ किसी भी चुनाव में महत्वपूणज़ भूमिका निभाता है, लेकिन पिछले कुछ वषोज़ं में छात्र और युवा आंदोलनों के बढ़ते प्रभाव ने इसे और महत्वपूणज़ बना दिया है. शिक्षा, प्रतियोगी परीक्षाओं, पेपर लीक, रोजगार और भतीज़ प्रक्रिया से जुड़े मुद्दों को लेकर युवाओं में असंतोष कई बार बड़े आंदोलनों में बदल चुका है. हाल ही में पेपर लीक के मुद्दे पर हुए छात्र आंदोलनों के बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी युवा वगज़ की राजनीतिक ताकत चचाज़ में रही. उत्तर प्रदेश में बड़ी युवा आबादी को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में भी युवा मतदाताओं की भूमिका अहम मानी जा रही है. विपक्षी दल युवाओं से जुड़े मुद्दों को उठाकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं. प्रस्तावित आयोग का दायरा 16 से 35 वषज़ के युवाओं तक हो सकता है.

दिल्ली कैबिनेट ने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बिल को दी मंजूरी

नई दिल्ली. दिल्ली कैबिनेट ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली प्राइवेट यूनिवसिज़्टी बिल को मंजूरी दे दी है. इस फैसले के साथ राजधानी में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का रास्ता साफ हो गया है. बिल के कानून बनने से पहले इसे दिल्ली विधानसभा में पेश किया जाएगा. विधानसभा से पारित होने के बाद ही इसे लागू किया जाएगा. दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद ने कहा कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में कैबिनेट ने दिल्ली प्राइवेट यूनिवसिज़्टी बिल को मंजूरी देकर राजधानी में निजी विश्वविद्यालय लाने का रास्ता साफकर दिया है.

एक नजर में

निर्माणाधीन दीवार गिरने से 2 की मौत

नई दिल्ली. गुरुग्राम के डीएलएफ फेज-2 में एक प्राइवेट स्कूल में कंस्ट्रक्शन के काम के दौरान शुक्रवार को एक बड़ा हादसा हो गया. लगातार हो रही बारिश के बीच, स्कूल परिसर में एक पुरानी दीवार अचानक गिर गई, जिससे वहां काम कर रहे दो मजदूर मलबे के नीचे दब गए. सूचना मिलने पर पुलिस, जिला प्रशासन और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंचीं और तुरंत बचाव अभियान शुरू किया. हालांकि मलबे को हटाकर मजदूरों को बाहर निकाला गया, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी. यह हादसा डीएलएफ फेज-2 के वसंत वैली स्कूल में हुआ. स्कूल परिसर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, तभी अचानक एक पुरानी दीवार गिर गई. शुरुआती जांच से पता चलता है कि लगातार बारिश और इलाके में जलजमाव के कारण दीवार कमजोर हो गई थी, जिससे वह गिर गई. स्थानीय पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और रेस्क्यू टीमें मौके पर पहुंचीं. रेस्क्यू टीम ने मलबे से दोनों मजदूरों को बाहर निकाला, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. इसके बाद, दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया. पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और जांच शुरू कर दी है.

हरियाणा में आईपीएस कैडर की संख्या 153 हुई

पंचकूला. हरियाणा के पुलिस प्रशासनिक ढांचे में बड़ा बदलाव करते हुए केंद्र सरकार ने राज्य के भारतीय पुलिस सेवा (आईपीएस) कैडर की कुल अधिकृत पद संख्या 144 से बढ़ाकर 153 कर दी है। इससे हरियाणा के आईपीएस कैडर में नौ पदों की बढ़ोतरी हुई है। संशोधित कैडर में राज्य सरकार के अधीन 84 वरिष्ठ ड्यूटी पद निर्धारित किए गए हैं, जबकि सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों की संख्या 107 रखी गई है। केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग ने हरियाणा सरकार से परामर्श के बाद छह अगस्त को इसकी अधिसूचना जारी की। इसे भारतीय पुलिस सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) तृतीय संशोधन विनियम, 2026 नाम दिया गया है और यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रभावी हो गया है। अधिसूचना के मुताबिक हरियाणा आईपीएस कैडर की कुल अधिकृत संख्या अब 153 होगी। इससे पहले यह संख्या 144 थी।

आज का इतिहास

- 1967- आजादी के बाद पहली बार केंद्र सरकार को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा।
- 1973- दक्षिण कोरियाई राजनीतिज्ञ किम डेए-जुंग को केसीआईए ने टोक्यो में अपहरण किया गया।
- 1988- अफ़ग़ानिस्तान में 9 साल के युद्ध के बाद रूसी सेना की वापसी शुरू हुई।
- 1990- इराक़ के तत्कालीन तानाशाह सददाम ने घोषणा की कि उसने कुवैत को 19वें प्रांत के रुप में अपने देश का भाग बना लिया है।

ट्रंप ने दो नए कार्यकारी आदेशों पर किए हस्ताक्षर

- जन्म आधार पर नागरिकता सीमित करने का आदेश
- बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने का आदेश

वॉशिंगटन, 07 अगस्त. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म के आधार पर मिलने वाली नागरिकता को सीमित करने और बर्थ टूरिज्म पर रोक लगाने के लिए दो नये कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किये हैं. गौरतलब है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह कदम उस घटना के कुछ सप्ताह बाद उठाया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इस लंबे समय से चली आ रही संवैधानिक गारंटी को खत्म करने की उनकी पिछली कोशिश को रोक दिया था.

> ओवल के कार्यालय से अपने संबोधन में श्री ट्रंप ने कहा, यह काम सालों पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अब हम इसे कर रहे हैं. उन्होंने 150 साल पुराने इस नियम को खत्म करने की अपनी पिछली कोशिश को सुप्रीम कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने की आलोचना की. पहले कार्यकारी आदेश में कहा गया है, मेरे प्रशासन ने उन बुरे इरादे वाले विदेशी लोगों से होने वाले खतरों से बचाव किया है जो हमारे देश की उदारता का फायदा उठाकर अमेरिकी नागरिकों को धोखा देने की कोशिश करते हैं. पहला कार्यकारी आदेश उन गैर-नागरिक माता-पिता की श्रेणी का दायरा बढ़ाता है जिनके बच्चे जन्म के समय अपने आप अमेरिकी नागरिकता पाने के हकदार नहीं होंगे. इस आदेश के तहत अगर अमेरिका में पैदा हुए बच्चे के माता-पिता दोनों गैर-नागरिक हैं, तो उन्हें अपने आप नागरिकता नहीं मिलेगी.

दिल्ली विधानसभा में भिड़े आप-भाजपा विधायक

नई दिल्ली, 07 अगस्त. दिल्ली विधानसभा के मानसून सत्र में गुरुवार को 650 करोड़ रुपये के कथित दवा घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ. सदन में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का सिलसिला इतना बढ़ गया कि आम आदमी पाटीज़ के विधायक कुलदीप कुमार और बीजेपी विधायक रवि नेगी अपनी सीटों से उठकर आमने-सामने आ गए.

दोनों नेताओं के बीच तीखी बहस और नोकझोंक हुई. स्थिति बिगड़ती देख सदन में मौजूद अन्य विधायकों और अध्यक्ष को हस्तक्षेप करना पड़ा. इसके बाद दोनों पक्षों को शांत कराया गया. हंगामे के चलते विधानसभा की कायज़्वाही भी कुछ समय के लिए प्रभावित रही. विधानसभा में दवा घोटाले का मुद्दा उठाते हुए आम

- सदन में मचा हंगामा

आदमी पाटीज़ के विधायकों ने सरकार को घेरने की कोशिश की. आप विधायकों ने 650 करोड़ रुपये के दवा घोटाले को लेकर सवाल उठाए और स्वास्थ्य मंत्री के इस्तीफे की मांग की.

नेहा बोरा ने लगाया स्याही फेंकने का आरोप

रांची, 07 अगस्त. झारखंड में जेपीएससी परीक्षा में कथित अनियमितताओं के खिलाफ जारी छात्र आंदोलन के दौरान अखिल भारतीय छात्र संघ की अध्यक्ष नेहा बोरा ने खुद पर स्याही फेंके जाने का आरोप लगाया है.

नेहा बोरा ने दावा किया कि बिरसा मुंडा स्टेडियम से माचज़ निकाले जाने के दौरान 26 वषीज़्य अमरनाथ पांडेय नाम के एक व्यक्ति ने उन पर स्याही फेंकी. उनके मुताबिक, प्रदशज़्न में

मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया. नेहा ने बताया कि वह अन्य साथियों के साथ माचज़ के दौरान खड़ी थीं, तभी अमरनाथ पांडेय नाम के युवक ने उन पर स्याही फेंक दी.

महबूबा मुफ्ती की बेटी पर एफआईआर

श्रीनगर. जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 से जुड़े मुद्दे को लेकर हुए प्रदशज़्न के दौरान पुलिस और प्रदशज़्नकारियों के बीच हुई झड़प अब कानूनी विवाद में बदल गई है. पीपुल्स डेमोक्रेटिक पाटीज़ की नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ श्रीनगर पुलिस ने एफआईआर दजज़ की है. मामला 4 अगस्त को हुए प्रदशज़्न से जुड़ा है, जहां पुलिस ने प्रदशज़्नकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया था. इसी दौरान इल्तिजा मुफ्ती और पुलिस अधिकारियों के बीच कथित तौर पर तीखी बहस हुई.

अमित शाह बोलेंगे तो सुन नहीं पाओगे

नई दिल्ली, 07 अगस्त. विपक्षी सांसदों ने शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा में राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर जमकर नारेबाजी की है. जिसके चलते दोनों सदनों

- विपक्ष पर रिजिजू का हमला

की कायज़्वाही स्थगित कर दी गई.

विपक्षी सांसदों ने राज्यसभा में 'अमित शाह सदन में आओ' के नारे लगाए. जिस पर संसदीय कायज़्मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा विपक्ष के सांसद सदन में आते हैं और नारेबाजी करके चले जाते हैं. लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चचाज़ का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा. हंगामे के बीच किरण रिजिजू ने कहा 'ये लोग (विपक्ष) के सांसद हर दिन सुबह आते हैं. सदन में गृहमंत्री अमित शाह का नाम लेकर नारे लगाते हैं और हंगामा करके गायब हो जाते हैं. लेकिन मैं बताना चाहूंगा कि गृह मंत्री अमित शाह सुबह-सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं. वह दिनभर संसद में ही रहते हैं.

>
> रिजिजू ने कहा 'विपक्ष किसी को आदेश नहीं दे सकता. आप निदेज़्श नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है. यह तय करना सरकार का काम होता है, आसन यह तय करता हैं. लेकिन यह लोग सदन को बाधित करके लगातार देश को गुमराह करने में लगे हैं. इसलिए यह नाटक बंद करना चाहिए.

हस्तियों के ट्वीट

भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने हाल ही में सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए कहा कि भारत की असली ताकत न सिर्फ इसकी विविधता में है, बल्कि उन कुशल हाथों में भी है जो इसे संजोकर रखते हैं. राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर, हम अपने उन प्रतिभाशाली बुनकरों का सम्मान करते हैं जिनकी कारीगरी हमारी समृद्ध वस्त्र-विरासत को पीढ़ियों से जीवित रखे हुए है. आइए, हम अपने बुनकरों का समर्थन करें और भारत की विरासत को वोकल फॉर लोकल से लोकल टू ग्लोबल तक ले जाने में मदद करें.

देश के गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुदेव टैगोर की जयंती पर नमन करते हुए अपने विचार वयक्त किये. उन्होंने सोशल मिडिया एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए लिखा कि कविगुरु गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर जी की पुण्यतिथि पर उन्हें कोटि-कोटि नमन. गुरुदेव टैगोर ने अपनी लेखनी से भारत की आत्मा को स्वर दिया और स्वतंत्रता आंदोलन में नई चेतना का संचार किया.

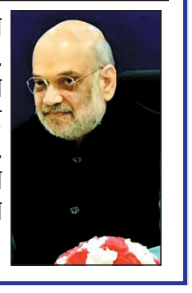

प्रदर्शन | लोस में नेता प्रतिपक्ष के घर के बाहर विरोध, कई प्रदर्शनकारी हिरासत में

राहुल गांधी के आवास के बाहर पुलिस ने बढ़ाई सुरक्षा

नई दिल्ली, 7 अगस्त. अयोध्या स्थित श्री राम मंदिर के चढ़ावा चोरी मामले को लेकर दिए गए बयानों के विरोध में शुक्रवार को लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के दिल्ली स्थित आवास के बाहर कुछ साधु-संतों और अन्य लोगों ने प्रदर्शन की कोशिश की.

प्रदर्शन की सूचना मिलने के बाद दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के आवास के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी और अतिरिक्त पुलिस बल के साथ अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की. पुलिस के अनुसार, प्रदर्शन के दौरान कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया. प्रदर्शनकारियों में कुछ साधु-संत भी शामिल थे. पुलिस ने उन्हें आवास की ओर बढ़ने से रोका और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक कार्रवाई की.

घटना के दौरान इलाके में सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया और आवास के आसपास निगरानी भी तेज कर दी गई. यह विरोध अयोध्या के श्री राम मंदिर में चढ़ावा चोरी से जुड़े मामले पर हाल में हुई राजनीतिक टिप्पणियों के बाद सामने आया. प्रदर्शनकारियों का आरोप था कि इस मुद्दे को राजनीतिक रूप दिया गया और धार्मिक आस्था से जुड़े विषय को संसद के भीतर और बाहर राजनीतिक बहस का हिस्सा बनाया गया.

कल प्रयागराज में छात्रों से करेंगे संवाद

प्रयागराज. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं को लेकर शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए प्रयागराज दौरे की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि वह 8 अगस्त को प्रयागराज में छात्रों से संवाद करेंगे. राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, नेट हो या अन्य भर्ती परीक्षाएं, दाल में काला नहीं, पूरी दाल ही काली है. उन्होंने कहा कि प्रयागराज देश का वह शहर है, जहां सबसे अधिक युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं और यहां का हर छात्र जानता है कि व्यवस्था ईमानदार नहीं रह गई है. उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को पेपर लीक, भर्ती प्रक्रियाओं में देरी, वर्षों तक इंतजार और जवाबदेही के अभाव जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है. राहुल गांधी ने कहा कि छात्रों की मेहनत में कोई कमी नहीं है, बल्कि समस्या उस व्यवस्था की है, जो उनकी मेहनत का उचित सम्मान नहीं करती.

होर्मुज पर ईरान की नई चाल

तेहरान, 07 अगस्त. ईरान होर्मुज जलडमरूमध्य से अमेरिका, इजरायल तथा अन्य दुश्मन देशों के जहाजों को गुजरने पर प्रतिबंध लगाने लिए एक विधेयक लाने की तैयारी कर रहा है और मौजूदा समय में ईरानी सांसद इसकी समीक्षा कर रहे हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार अगर ईरानी संसद इस प्रस्तावित विधेयक को मंजूरी प्रदान कर देती है, तो यह होर्मुज जलडमरूमध्य और फारस की खाड़ी में सुरक्षा, नेविगेशन और आर्थिक गतिविधियों के प्रबंधन के लिए एक रणनीतिक ढांचा तैयार करेगा. ग्यारह अनुच्छेद वाले इस शुरुआती प्रस्ताव से ईरानी अधिकारियों को समुद्री ट्रैफ़िक पर ज़्यादा अधिकार मिलेंगे.